

भारत की वदिश नीति

प्रलिमिंस के लिये:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA), मानवाधिकार आयोग

मेन्स के लिये:

भारत की वदिश नीति की वर्तमान चुनौतियाँ और आगे की राह

चर्चा में क्यों?

भू-राजनीतिक और कूटनीतिक मंच के संदर्भ में वर्ष 2022 वशिष रूप से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद एक कठिन वर्ष रहा है।

यूक्रेन संकट और भारत:

- गुटनरिपेक्षता नीति का पालन:
 - यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने "गुटनरिपेक्षता" के अपने संस्करण को परभाषित किया, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते ध्रुवीकरण एवं रूस के संदर्भ में संतुलन बनाने की मांग की।
 - एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि "यह युग युद्ध का नहीं है", रूसी राष्ट्रपति व्लादमिर पुतिन से युद्ध को लेकर अपनी चिंता स्पष्ट कर दी और दूसरी ओर रूस के साथ बढ़ते सैन्य एवं तेल व्यापार पर पश्चिमी प्रतिबंधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, साथ ही उन्हें सुवर्धाजनक बनाने के लिये रुपया आधारित भुगतान तंत्र की मांग की।
- प्रस्ताव पर वोट देने से इनकार करना:
 - सबसे महत्वपूर्ण रूप से जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council- UNSC), संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly- UNGA), अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency- IAEA), मानवाधिकार आयोग और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों में आक्रमण एवं मानवीय संकट के लिये रूस की नदिा करने की मांग की गई तो भारत ने मामले से दूर रहने का विकल्प चुना।
 - भारतीय वदिश नीति का दावा है कि भारत की नीति राष्ट्रीय हितों पर निर्धारित की गई थी, भले ही देशों ने भारत से पक्ष लेने की उम्मीद की थी लेकिन भारत की नीतियाँ उन देशों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं।

वदिश नीति 2022 की अन्य प्रमुख वशिषताएँ:

- मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements- FTAs) को अपनाना:
 - कई वर्षों के अंतराल के बाद सभी द्विपक्षीय नविश संधियों (Bilateral Investment Treaties- BITs) को रद्द करने और 15 देशों की एशियाई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) से हटने के बाद सभी मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा करने के पश्चात् वर्ष 2022 में भारत पुनः FTA में शामिल हो गया।
 - वर्ष 2022 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये एवं इस संदर्भ में यूरोपीय संघ, खाड़ी सहयोग परिषद तथा कनाडा के साथ बातचीत पर प्रगति की उम्मीद है।
- अमेरिकी नेतृत्व वाले IPEF में शामिल:
 - भारत, अमेरिका के नेतृत्व वाले इन्डो-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (Indo-Pacific Economic Forum- IPEF) में भी शामिल है, हालाँकि बाद में उसने व्यापार वार्ता से बाहर रहने का फैसला किया।

पड़ोसियों के साथ संबंध:

- श्रीलंका:
 - भारत ने अपनी वदिश नीति के तहत श्रीलंका के पतन के दौरान उसे आर्थिक सहायता प्रदान की।

- **बांग्लादेश, भूटान और नेपाल:**
 - भारत की वदेश नीतिको बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ क्षेत्रीय व्यापार एवं ऊर्जा समझौतों द्वारा चहिनति कथिा गया है , जससे दक्षिण एशियाई ऊर्जा ग्रिड का विकास संभव हो सकेगा ।
- **मध्य एशियाई देश:**
 - कनेक्टिविटी को लेकर भारत ने **मध्य एशियाई देशों** के साथ भी संबंध मजबूत कथिे हैं ।
 - भारत ने बहुप्रीकषति **तुरकमेनसितान-अफगानसितान-पाकसितान-भारत (TAPI)** पाइपलाइन परयोजना को पुनरस्थापति करने के प्रयासों को फरि से शुरू कर दथिा है ।
 - भारत ने **इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर** (International North-South Transport Corridor- INSTC) के बेहतरीन इस्तेमाल पर भी चर्चा की ।
 - ईरान में **चाबहार बंदरगाह** को शुरू करने के लथिे भी कदम उठाए गए हैं जो मध्य एशियाई देशों के लथिे समुद्र तक एक सुरक्षति, व्यवहार्य और अबाध पहुँच प्रदान कर सकता है ।
- **अफगानसितान और म्याँमार:**
 - सरकार ने अफगानसितान के तालबान और म्याँमार में जुंटा जैसे दमनकारी शासनों के लथिे बातचीत के रास्ते खुले रखे, काबुल में "तकनीकी मशिन" शुरू कथिा एवं सीमा सहयोग पर चर्चा करने के लथिे वदेशि सचवि को म्याँमार भेजा गया ।
 - इससे पहले दसिंबर 2022 में **म्याँमार में हसिा को समाप्त करने और राजनीतिक कैदथिों को रहिा करने के लथिे की गई UNSC वोटगि में भारत ने भाग नहीं लथिा था ।**
- **ईरान और पाकसितान:**
 - ईरान में भी एक कार्यकरत्ता की हत्या के वरिध में जब हज़ारों लोग सड़कों पर उतरे, भारत ने कसिी भी तरह की आलोचना करने से परहेज कथिा ।
 - हालाँकि दोनों देशों के वदेशि मंत्रथिों के बीच दसिंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र में एक बड़े शक्ति-परीक्षण के बाद पाकसितान के साथ संबंध सामान्य बने हुए हैं ।

LAC-चीन गतरिध में वृद्धि:

- चीन के वदेशि मंत्री की दलिली यात्रा एवं **वासुतवकि नथितरण रेखा (LAC)** पर कुछ गतरिध बढिओं पर उसके पीछे हटने के बावजूद तनाव बना रहा और अरुणाचल प्रदेश के यांग्तसे में भारतीय चौकथिों पर कब्ज़ा करने के चीनी PLA के असफल प्रयास के साथ इस वर्ष की समाप्त हुई, यह वर्ष 2023 में चीन के साथ और अधिक हसिक झड़प होने का संकेत है ।
- संबंधों की कठनि स्थथितथिों के बावजूद भारत वर्ष 2023 में दो बार **जी-20** और **SCO शखिर सम्मेलन** में चीनी राष्ट्रपति की उपस्थति में मेज़बानी करने वाला है, इससे गतरिध समाप्त करने के लथिे वार्ता की राह खुलने की संभावना है ।

भारत की वदेशि नीतिकी वर्तमान चुनौतथिाँ:

- **पाकसितान-चीन सामरकि गठजोड़:**
 - आज भारत जसि सबसे वकिट खतरे का सामना कर रहा है, वह है पाकसितान-चीन सामरकि गठजोड़, जो वविादति सीमाओं पर यथास्थति को बदलना चाहता है और भारत की सामरकि सुरक्षा को कमज़ोर करना चाहता है ।
 - वासुतवकि नथितरण रेखा (LAC) पर यथास्थति को बदलने के लथिे मई 2020 से चीन की आकरामक कार्रवाइयों ने चीन-भारत संबंधों को गंभीर नुकसान पहुँचाया है ।
- **चीन की वसितारवादी नीति:**
 - दक्षिण एशिया और **हदि महासागर क्षेत्र** में चीन के **वर्चस्व को संतुलति करने का मुद्दा**, भारत के लथिे एक और चतिा का वषिय है ।
 - चीन के बहुप्रीकषति **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिवि (BRI)** के तहत यह पाकसितान में **चीन-पाकसितान आर्थकि गलयारा (CPEC)** वकिसति कर रहा है (पाकसितान अधकृत कश्मीर में भारतीय क्षेत्र पर), यह चीन-नेपाल आर्थकि गलयारा, चीन-म्याँमार आर्थकि गलयारा का नरिमाण हदि महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में दोहरे उपयोग के लथिे कर रहा है ।
- **शक्तिशाली देशों के साथ शक्ति संतुलन:**
 - भारत की रणनीतिक स्वायत्तता भारत को उस कसिी भी सैन्य गठबंधन या रणनीतिक साझेदारी में शामिल होने से रोकती है जो कसिी अन्य देश या देशों के समूह के लथिे शत्रुतापूर्ण है ।
 - परंपरागत रूप से पश्चिमि ने भारत को सोवयित संघ/रूस के करीब माना है । इस धारणा को भारत द्वारा SCO, **BRICS** और **रूस-भारत-चीन (RIC)** फोरम में सकरथि रूप से भाग लेने से बल मलिया है ।
 - भारत को हठधरमी चीन को संतुलति करने, पाकसितान-चीन हाइब्रिड खतरों से उत्पन्न सुरक्षा दुवधियाँ को दूर करने के लथिे भारत-प्रशांत क्षेत्र में बाह्य संतुलन पर नरिभर रहना होगा ।
 - अमेरिका, जापान, फ्रांस, बरटिन और इंडोनेशिया के साथ मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले **QUAD** में भारत की भागीदारी को भी इस नज़रथिे से देखा जाना चाहथिे ।
- **शरणार्थी संकट:** वर्ष **1951 के शरणार्थी सम्मेलन** और 1967 प्रोटोकॉल के पक्ष में नहीं होने के बावजूद विश्व में भारत में शरणार्थियों की बहुत बड़ी संख्या नविस करती है ।
 - यहाँ चुनौती मानवाधिकारों के संरक्षण और राष्ट्रीय हति में संतुलन बनाने की है । जैसे कि रोहगिया संकट मुद्दे पर अभी भी बहुत कुछ कथिा जाना है, इस स्थथिे में भारत को दीर्घकालिक समाधान खोजने की आवश्यकता है ।
 - भारत की क्षेत्रीय और वैश्वकि स्थथितिको नरिधारति करने में मानवाधिकारों के मुद्दे पर की गई कार्रवाइयाँ महत्त्वपूर्ण होंगी ।

आगे की राह

- भारत को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिये आगे आना चाहिये जो भारत के [समावेशी विकास](#) के लिये अनुकूल हो ताकि विकास का लाभ देश के गरीब-से-गरीब व्यक्ति तक पहुँच सके।
 - यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज़ सुनी जाए एवं [आतंकवाद](#), [जलवायु परिवर्तन](#), नरिस्त्रीकरण, वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत विश्व जनमत को प्रभावित करने में सक्षम हो।
- जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि **सिद्धांतों और नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारी होगी। भारत को बड़े पैमाने पर दुनिया में अपने नैतिक नेतृत्व को पुनः प्राप्त करते हुए एक नैतिक अनुनय के साथ सामूहिक विकास की ओर बढ़ना चाहिये।**
- अतः भारत की विदेश नीति बदलती परिस्थितियों के अनुसार तेज़ी से प्रतिक्रिया करने के लिये सक्रिय, लचीली व व्यावहारिक होनी चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध अन्य राष्ट्रों के हितों की परवाह किये बिना अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने की नीति पर संचालित होते हैं। इससे राष्ट्रों के बीच संघर्ष और तनाव पैदा होता है। नैतिक विचार ऐसे तनावों को हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं? विशिष्ट उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. भारत-श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में चर्चा करें कि घरेलू कारक विदेश नीति को कैसे प्रभावित करते हैं। (2013)

प्रश्न. 'उत्पीड़ित और उपेक्षित राष्ट्रों के नेता के रूप में भारत की लंबे समय से चली आ रही छवि, उभरती वैश्विक व्यवस्था में इसकी नई भूमिका के कारण गायब हो गई है।' वसित्त व्याख्या कीजिये। (2019)

[स्रोत: द द्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/foreign-policy-of-india>

